



किसानों का भोपाल कूच : बैरिकेड तोड़े, वैकल्पिक रास्ता चुना, 500 से ज्यादा अन्नदाता पैदल निकले : आठ सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

एक्शन इंडिया

वर्ष: 15 अंक: 210 पृष्ठ: 08

RNI : HPHIN/2012/48072



actionindiauna@gmail.com

हिमाचल संस्करण

दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड - चंडीगढ़



केंद्र सरकार ने एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया: अखिलेश यादव

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। लोकसभा में पेपर लोक रोकने से जुड़े संशोधन विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नीट-यूजी 2026 परीक्षा में कथित

गड़बड़ियों के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन का नतीजा बताया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों युवाओं के दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा और अब सरकार को आंदोलन के दौरान किए गए सभी आश्वासन भी

कसा तंज

करोड़ों युवाओं के दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा और अब सभी आश्वासन भी सार्वजनिक करने चाहिए।



अखिलेश यादव ने कहा कि वह शुरू से इस आंदोलन को देख रहे थे। उनके मुताबिक, आंदोलन के बाद एक नारा सबसे ज्यादा सुनाई दिया कि सरकार को लगता था वह कभी नहीं झुकेगी, लेकिन युवाओं ने साबित कर दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की

पहली बड़ी मांग स्वीकार करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अन्य मांगों पर भी सहमति बनाई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि उन आश्वासनों को संसद के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान मंत्री पद छोड़ने के बाद संसद पहुंचे तो

उनका स्वागत हुआ, लेकिन इस फैसले से सदन के कई सदस्यों ने राहत की सांस ली होगी। क्या छात्र आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया? अखिलेश यादव ने कहा कि यह पहला ऐसा छात्र आंदोलन था, जिसमें केवल छात्र ही नहीं बल्कि उनके माता-पिता भी खुलकर साथ आए।

फास्ट न्यूज

अगले 6 दिनों तक भारी वर्षा से राहत के आसार नहीं

नई दिल्ली। देश के पूर्वोत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों को अगले 5-6 दिनों तक मूसलाधार वर्षा से राहत नहीं मिलने के आसार हैं। बचाव टीमों संभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। रात में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। तेज रफ्तार हवाएं भी चलने की संभावना है। इस दिन का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 32-34 डिग्री सेल्सियस और 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 30 एवं 31 जुलाई को भी यही स्थिति बनी रहेगी लेकिन इन दोनों दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी इलाकों और उससे सटे गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल पर बने गहरे दबाव के असर से छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में 29 जुलाई, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 30 जुलाई और गुजरात क्षेत्र में 31 जुलाई को कहीं-कहीं बहुत अधिक बारिश (21 सेमी) होने की संभावना है। देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों में अगले 5-6 दिनों के दौरान बहुत अधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।

जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

टोक्यो। जापान के क्यूशू द्वीप के कुमामोटो इलाके में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें कई लोगों के घायल होने की आशंका है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गयी है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) के अनुसार, स्थानीय समयानुसार शाम 4:27 बजे आए इस भूकंप का केंद्र कुमामोटो प्रांत में लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था।

पेपर लोक, नकल माफिया और दोषी संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई की तैयारी, सजा और जुर्माने में होगा बड़ा इजाफा

परीक्षाओं में नकल पर अब और कड़ा शिकंजा, संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

संसद में चर्चा

अधिकतम सजा 10 वर्ष तक और जुर्माना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक



पीएम को कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा: प्रियंका

लोकसभा में मंगलवार को पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। संसद में प्रियंका गांधी ने कहा कि बच्चों पर लाठियां किसके आदेश पर चलाए गए, यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है, अध्यापक, छात्र, माता-पिता पूछ रहे हैं सिर्फ कांग्रेस नहीं पूछ रही है। ये सदन सांसदों की जागीर नहीं है। मंगलवार को संसद में प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत एक घटना से की। जब मैं एक छायाल छात्रा से मिलने गए, तो उसकी मां बोली- सुबह से बड़े-बड़े नेता आए। वह भी आए जिनकी

के लिए संशोधन प्रस्तावित किया गया है। प्रमुख राष्ट्रीय परीक्षाएं पहले से कानून के दायरे में मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 का

कानून संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) जैसी प्रमुख संस्थाओं की परीक्षाओं पर लागू किया गया था। इसके तहत परीक्षा संबंधी अपराधों को सज्जै, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य बनाया गया था, ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

सजा और जुर्माने में बड़ा इजाफा संशोधन विधेयक के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों के लिए न्यूनतम सजा तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने तथा अधिकतम सजा दस वर्ष तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही अधिकतम जुर्माना लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि कठोर दंड से परीक्षा माफिया और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

सेवा प्रदाताओं और कंपनियों पर भी होगी कार्रवाई सेवा प्रदाताओं की परिभाषा का विस्तार करते हुए परीक्षा आयोगन से जुड़े संस्थानों, कंपनियों, साझेदारी फर्मों, ठेकेदारों और तकनीकी सेवा प्रदाताओं को भी कानून के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। यदि कोई संस्था दोषी पाई जाती है तो उस पर अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।



आईसीजी ने महिलाओं को बराबर मौके देने के लिए शुरु किया 'जेंडर न्यूट्रल प्रेमवर्क'।

पेपर लोक पर संशोधन विधेयक से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी: गौरव गोगोई

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केवल कानूनों में संशोधन करने से परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं होगा। सरकार को परीक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को दूर करने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार नए कानून लाने के बजाय परीक्षा प्रणाली की खामियों को दूर करने पर ध्यान दे। उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक परीक्षा संस्थानों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक वास्तविक सुधार संभव नहीं है।

दिल्ली की महिलाओं को हर महीने मिलेगी 2500 रुपए



टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस बहुप्रतीक्षित योजना पर मंजूर लगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 की सम्मान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली की महिलाओं के लिए

लक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी। 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू होगा

ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान महिलाओं से किया गया वादा अब पूरा हो गया है और सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

शिक्षकों को बीएलओ बनाया जा सकता है लेकिन उन पर अनावश्यक दबाव न हो: कोर्ट

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान निर्वाचन आयोग स्कूलों के शिक्षकों को बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) के रूप में तैनात कर सकता है लेकिन इससे शिक्षकों के ऊपर अनावश्यक तनाव नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने मंगलवार को ये टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती करते समय शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो किसी भी शिक्षक को स्कूल के टाइम में उनकी कोई सेवा नहीं लेगा।

भारत की पाकिस्तान को दो टूक, खारिज किए पीओजेके के चुनाव

कड़ी प्रतिक्रिया

भारत ने चुनावों से जुड़ी खबरें देखी हैं और यह पाकिस्तान के अवैध कब्जे को वैध दिखाने की है



टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश

मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इन चुनावों से जुड़ी खबरें देखी हैं और यह पूरी कवायद पाकिस्तान के अवैध कब्जे को

वैध दिखाने की कोशिश है। रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों से

जुड़ी खबरें देखी हैं। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो इस समय पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे में हैं, भारत के अभिन्न अंग हैं।" विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "यह मौजूदा दिखावटी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर पर्दा डालने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों को छिपाने की एक कोशिश मात्र है।"

प्रकृति संरक्षण में ही मानवता का कल्याण निहित: प्रधानमंत्री मोदी

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रकृति के संरक्षण और उसके सम्मान को मानवता के कल्याण निहित है। वह कल्याण का आधार बताते हुए मंगलवार को एक्स पर सुभाषित-साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन जीने की प्रेरणा

देती है। प्रधानमंत्री ने लिखा, "प्रकृति के संरक्षण और सम्मान में ही मानवता का कल्याण निहित है। वह सुभाषितम् है, "लोकपालाश्च ते सर्वे वासवप्रमुखस्तास्था। ऋतवः षट् च ते सर्वे मासाः संवत्सराः क्षपाः॥ दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा। श्रुतिः स्मृतिश्च धर्मश्च पातु त्वां पुत्र सर्वतः॥"

असम में बाढ़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले सांसद, राहत कार्यों की समीक्षा

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। असम के सांसदों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात कर राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों तथा प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के उपायों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने राहत कार्यों का दिया भरोसा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने असम के सांसदों के साथ राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, असम सरकार के



साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कुशलक्षेम की भी कामना की। लगातार बारिश से पूर्वोत्तर में हालात गंभीर पिछले कई दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण पूर्वोत्तर

भारत के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। असम के अनेक जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। बाढ़ के कारण सामान्य जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

नामांकन

सरकारी विद्यालयों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है

टीम एक्शन इंडिया पंजाब शर्मा शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालय आगामी पांच वर्षों में राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में उभरेंगे। मुख्यमंत्री ने आज शिमला स्थित बिशप कॉटन स्कूल (बीसीएस) के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए



कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। इसी दृष्टिकोण के तहत सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया गया है तथा 156 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने

आए हैं और सरकारी विद्यालयों में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के आदर्श केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है क्योंकि यहां के शैक्षणिक वातावरण में विद्यार्थियों को आगे बढ़? के लिए श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने

कहा कि बिशप कॉटन स्कूल केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि उत्कृष्टता, नेतृत्व, अनुशासन और चरित्र निर्माण की जीवंत परंपरा का प्रतीक है। इस संस्थान ने पीढ़ी ें से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने इस संस्थान से जुड़े व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि कॉलेज जीवन के दौरान बिशप कॉटन स्कूल में वे कई बार क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आए थे, इसलिए इस विद्यालय से उनका विशेष जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी शिमला के प्रतिष्ठित संस्थानों की बात होती है, तो बिशप कॉटन स्कूल का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इस विद्यालय के

पूर्व विद्यार्थियों ने देश-विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर संस्थान का नाम गौरवान्वित किया है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अवसर केवल विद्यालय की स्थापना का उत्सव नहीं है, बल्कि उन शाश्वत मूल्यों को स्मरण करने का भी अवसर है जिन पर इस महान संस्थान की नींव रखी गई थी। उन्होंने कहा कि समय परिवर्तनशील है और बदलते समय के साथ-साथ नित नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। वर्तमान में ईमानदारी, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और सेवा जैसे मूल्यों की प्रासंगिकता बढ़ी है।

नौकरी ढूढ़ने नहीं, नौकरी देने की सोच पैदा कर रहा 'यूथ अड्डा'

❑ 'यूथ अड्डा' के जरिए नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी सरकार, युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने के लिए की गई महत्वपूर्ण पहल, नई पीढ़ी की बदलती आकांक्षाओं को पहचानकर सीएम योगी ने उठाया दूरदर्शी कदम, युवाओं के लिए उद्यमिता का नया इकोसिस्टम तैयार करना है योगी सरकार की पहल का उद्देश्य, यूथ अड्डा को प्रदेश भर में उद्यमिता के एक सशक्त मंच के रूप में विकसित कर रहा यूपीकोंन

अभिनव

❑ युवाओं को उद्यमी बनाने की सोच के साथ सीएम युवा और यूथ अड्डा जैसी अभिनव अवधारणा को विकसित किया

टीम एक्शन इंडिया
लखनऊ: आज की जेनरेशन जेड पारंपरिक नौकरी की तलाश तक सीमित नहीं रहना चाहती। यह पीढ़ी नवाचार, तकनीक, स्टार्टअप, डिजिटल बिजनेस और आत्मनिर्भरता में अपना भविष्य देखती है। जिन युवाओं का जन्म 1997 के बाद हुआ, वे इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल तकनीक के साथ बड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें केवल रोजगार नहीं, बल्कि अवसर, मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और उद्यमिता का पूरा इकोसिस्टम चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बहुत पहले समझ लिया था। यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने केवल रोजगार योजनाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि युवाओं को उद्यमी बनाने की सोच के साथ सीएम युवा और यूथ अड्डा जैसी अभिनव अवधारणा को विकसित किया। इसका उद्देश्य



योगी सरकार की उपलब्धि: 7 लाख से अधिक आवासीय रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में यूपी दूसरे स्थान पर

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने इस महत्वाकांक्षी योजना को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। यूपीनेडा, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सभी डिस्कॉम, राज्य

स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंकिंग संस्थानों, जनपदीय प्रशासन, विद्युत विभाग, सौर ऊर्जा उद्योग तथा अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी रूफटॉप सोलर राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुका है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद 7 लाख से अधिक आवासीय रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का दूसरा



राज्य बन गया है। जुलाई 2026 तक राज्य में 11,58,183 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 7,03,661 से अधिक आवासीय रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन संयंत्रों के माध्यम से 2371.14 मेगावाट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है। केवल ढाई वर्षों में प्राप्त यह उपलब्धि उत्तर

प्रदेश की दूरदर्शी नीतियों, प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल पारदर्शिता, सुदृढ़ संस्थागत समन्वय तथा प्रदेशवासियों की बढ़ती सहभागिता का प्रमाण है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही आकर्षक सब्सिडी, सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पारदर्शी पोर्टल आधारित मॉनिटरिंग तथा मजबूत कार्यान्वयन व्यवस्था ने योजना को अभूतपूर्व गति प्रदान की है।

जेई-ईएस को लेकर अलर्ट हुई योगी सरकार, प्रभावित हर गांव तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल

टीम एक्शन इंडिया
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के संकल्प को और गति देते हुए योगी सरकार ने जापानी इसेफेलाइटिस (जेई) और एक्यूट इसेफेलाइटिस सिंड्रोम (ईएस) प्रभावित गांवों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में कार्य करने का खाका तैयार किया है। इसी क्रम में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्रभावित गांवों में अभी तक नल से जलापूर्ति शुरू नहीं हो पाई है, वहां 24 घंटे में तीन शिफ्टों में काम पूरा कर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर प्रभावित गांव तक सुरक्षित पेयजल पहुंचे, जिससे जलजनित बीमारियों की रोकथाम के साथ ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।

गुणवत्ता और समयबद्धता पर सरकार का फोकस

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक के

दौरान जलशक्ति मंत्री ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत कराने के निर्देश

जलशक्ति मंत्री ने अधिकारियों को नियमित रूप से गांवों का भ्रमण कर पेयजल योजनाओं की प्रगति की निगरानी करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सिंगल विलेज योजनाओं के सभी लॉबित कार्य तय समय में पूरे किए जाएं। पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की तुरंत मरम्मत कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी, सड़क मरम्मत या अन्य कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने किसानों को दिलाया भरोसा-

परेशान न हों, प्रदेश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध

टीम एक्शन इंडिया
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार वर्तमान खरीफ सीजन में मुख्य फसल धान की रोपाई और अन्य फसलों की बुवाई के उपरांत किसानों को फसल संस्तुति के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि परेशान न हों, प्रदेश में उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि व संबंधित विभाग के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान



भ्रामक सूचनाओं व अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से उर्वरक भंडारण न करें। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक उर्वरक उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

प्रदेश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध: कृषि मंत्री

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने

बताया कि प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। खरीफ सीजन- 2026 के तहत सोमवार (27 जुलाई) तक कुल 28.25 लाख मीट्रिक टन उर्वरक बिक्री की जा चुकी है, जबकि 29.05 लाख मीट्रिक टन उर्वरक अब भी उपलब्ध है। सरकार किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

हरियाणा के कॉलेजों में पीजी के

दाखिलों का नया कार्यक्रम जारी

टीम एक्शन इंडिया
चंडीगढ़। हरियाणा में स्नातकोत्तर (पीजी) प्रथम वर्ष के दाखिलों को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने संशोधित प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के तहत अब मेरिट सूची, फीस जमा करने और फिजिकल काउंसिलिंग की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से अगस्त माह में पूरी होगी। विभाग ने सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को संशोधित कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नए कार्यक्रम का उद्देश्य दस्तावेज सत्यापन, आपत्तियों के निस्तारण और खाली सीटों पर पारदर्शी तरीके से प्रवेश सुनिश्चित करना है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण 7 अगस्त तक और आवेदन में संशोधन 8 अगस्त तक किया जा सकेगा।

कॉलेज 9 अगस्त तक दस्तावेजों का सत्यापन और आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। इसके बाद 10 अगस्त को पहली प्रॉविजनल मेरिट सूची तथा 11 अगस्त को फाइनल मेरिट सूची जारी होगी। प्रथम चरण के चयनित अभ्यर्थियों को 12 से 14 अगस्त तक फीस जमा करनी होगी। इसके बाद बची हुई सीटों के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 अगस्त को फिजिकल काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी ताकि रिक्त सीटों को शीघ्र भरा जा सके। जो विद्यार्थी पहली प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर सके, उन्हें एक और अवसर दिया गया है। 16 अगस्त को ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, जहां 100 लेट फीस के साथ नया पंजीकरण और आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा।

हरियाणा में रेडियोग्राफर होंगे रेडियोलॉजी अधिकारी

स्वीकृति

❑ पैर-मेडिकल और विविध पद (राज्य समूह-सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई

हो गए थे। ये पद विभाग में कार्यरत पात्र रेडियोग्राफरों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं। संशोधित नियमों के तहत, 22 स्वीकृत पदों के साथ सेवा नियमों में वरिष्ठ रेडियोलॉजी अधिकारी की एक नई श्रेणी शुरू की गई है। यह पद स्नक्करू-6, सेल-टू (35,400 रुपये - 1,12,400 रुपये) का वेतनमान वहन करेगा और इसे मुख्य रूप से निर्धारित योग्यताओं और न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले रेडियोलॉजी अधिकारियों में से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के माध्यम से नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने पूरे सेवा नियमों में नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक परिशिष्टों सहित 'रेडियोग्राफर' पदनाम को बदलकर 'रेडियोलॉजी अधिकारी' करने वाले संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, संशोधित नियमों में मौजूदा सरकारी नीतियों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नियुक्तियों में आरक्षण, सीधी भर्ती में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अनुभव में छूट, पात्रता शर्तों और नागरिकता आवश्यकताओं से संबंधित संशोधित प्रावधान शामिल हैं।

हरियाणा: 60 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में एमएसएमई एवं निर्यात क्षेत्र के लिए 60 परिवर्तनकारी पहलें



टीम एक्शन इंडिया
चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एवं विकसित भारत-2047 की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से प्रेरित होकर, हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व एवं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नखीर सिंह के मार्गदर्शन में आज हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति2026 का अनावरण किया। यह नीति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एएमएसएमई) के लिए राज्य का अब तक का सर्वाधिक महत्वाकांक्षी नीतिगत ढांचा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निरंतर इस बात पर बल दिया है कि एमएसएमई क्षेत्र भारत के विनिर्माण एवं औद्योगिक विकास की रीढ़ है तथा जब एमएसएमई आगे बढ़ते हैं, तभी भारत भी प्रगति करता है। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हरियाणा ने एमएसएमई क्षेत्र को अपनी विकास रणनीति के केंद्र में स्थान दिया है तथा इसे निवेश, नवाचार, रोजगार सृजन एवं निर्यात वृद्धि का प्रमुख

ऐतिहासिक नीति

❑ उद्यमिता, विनिर्माण, निर्यात एवं रोजगार को गति प्रदान करने हेतु एक ऐतिहासिक नीति

आधार माना है। हरियाणा अपनी विकास यात्रा के 60 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने प्रदेश के 14 लाख से अधिक एमएसएमई के पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 60 परिवर्तनकारी पहलों [1] को समर्पित किया है। इस नीति के माध्यम से अगले पाँच वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र में 755,000 करोड़ से अधिक के निवेश की आकर्षित करने, पाँच लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करने तथा हरियाणा के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माध्यम से हरियाणा को विनिर्माण, उद्यमिता एवं वैश्विक व्यापार के लिए भारत के सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी राज्यों में स्थापित करने का उद्देश्य है।

हरियाणा में बनेगा अल्पसंख्यक आयोग

टीम एक्शन इंडिया
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026 को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनके लिए उपलब्ध संवैधानिक एवं वैधानिक संरक्षणों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन करना है। आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य तथा सरकार द्वारा नियुक्त एक सचिव होगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों का

कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। विधेयक में उनके त्यागपत्र, पद से हटाने तथा रिक्त पदों को भरने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। आयोग अल्पसंख्यक समुदायों को प्राप्त संवैधानिक एवं वैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा तथा उनके प्रभावी पालन के लिए सरकार को आवश्यक सुझाव देगा। इसके अतिरिक्त, आयोग अल्पसंख्यकों से संबंधित सरकारी नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी करेगा, विभिन्न विषयों पर अध्ययन एवं अनुसंधान कराएगा, सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का आकलन करेगा तथा उनके कल्याण एवं विकास के लिए आवश्यक सिफारिशें करेगा।

हरियाणा में अब एक साल के लिए होगी पटवारी ट्रेनिंग

प्रशिक्षण

❑ पटवारियों के भर्ती और प्रशिक्षण ढांचे का आधुनिकीकरण करना, उनकी सेवा शर्तों में सुधार करना है

टीम एक्शन इंडिया
चंडीगढ़। हरियाणा में अब पटवारियों की ट्रेनिंग अवधि एक साल की होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राजस्व पटवारी (समूह-सी) सेवा नियम, 2011 में संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों का उद्देश्य राजस्व



पटवारियों के भर्ती और प्रशिक्षण ढांचे का आधुनिकीकरण करना, उनकी सेवा शर्तों में सुधार करना तथा राजस्व प्रशासन को अधिक कुशल और उत्तरदायी बनाना है। संशोधित नियम 1 जनवरी, 2025 से लागू माने जाएंगे।

मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया एक प्रमुख निर्णय- नए नियुक्त पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि को डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष करना है। संशोधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में पटवार स्कूल में छह महीने का

संस्थागत प्रशिक्षण और उसके बाद छह महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा। यह निर्णय राज्य स्तरीय पटवारी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है और इससे फील्ड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित पटवारियों की जल्द उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने नए नियुक्त पटवारियों की सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण सुधार को भी मंजूरी दी। प्रशिक्षण अर्वांध के दौरान वजीफा (स्टाडिपेंड) मिलने के बजाय, अब उन्हें फंक्शनल पे-लेवल-2 में 19,900 रुपये का शुरूआती वेतन दिया जाएगा।

प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारी बारिश के कारण कई सड़क मार्ग भी प्रभावित हुए हैं

टिहरी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, मिलंगना नदी उफान पर

परेशानी बढ़ी

❑ बंद मार्गों को जल्द खोलने के लिए संबंधित विभागों की मशीनें और टीमें लगातार कार्य कर रही हैं

टीम एक्शन इंडिया
टिहरी। टिहरी जिले में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से भिलंगना नदी उफान पर है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारी बारिश के कारण कई सड़क मार्ग भी प्रभावित हुए हैं।



जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के अनुसार मंगलवार सुबह तक जनपद में औसतन 67.23 मिमी बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक 109 मिमी बारिश टिहरी क्षेत्र में

हुई, जबकि धनोल्दी में 88 मिमी, कीर्तिनगर में 70 मिमी, नरेंद्रनगर में 63 मिमी, देवप्रयाग में 38.4 मिमी और घनसाली में 35 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। टिहरी बांध

का जलस्तर सुबह 8 बजे 789.20 मीटर दर्ज किया गया तथा 194 क्यूमेक्स पानी का डिस्चार्ज किया गया। भारी बारिश को देखते हुए घनसाली एसडीएम

मंजू राजपूत के निर्देश पर तहसील क्षेत्र के कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय मंगलवार को बंद रखे गए। बारिश के कारण ऋषिकेश-चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग-34 आमसरा के पास सुबह मलबा आने से बाधित हो गया था, जिसे करीब एक घंटे बाद खोल दिया गया। वहीं यमुना पुल-बड़कोट राष्ट्रीय राजमार्ग-507 और टिहरी-मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग-707ए पर भी भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुआ। टिहरी-मलेथा मार्ग को कुछ घंटों में खोल दिया गया, जबकि यमुना पुल-बड़कोट मार्ग देर शाम तक बाधित रहा। लोक निर्माण विभाग के अनुसार जिले में कुल 33

मोटर मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 26 को यातायात के लिए खोल दिया गया। देर शाम तक दो जिला मार्ग और पांच ग्रामीण मार्ग सहित सात सड़कें बंद रहें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत 19 ग्रामीण सड़कें बाधित हुईं, जिनमें आठ को सुचारू कर दिया गया, जबकि 11 सड़कें देर शाम तक बंद रहें। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट ने बताया कि जनपद में कहीं से भी विद्युत अथवा पेयजल आपूर्ति बाधित होने की सूचना नहीं मिली है। बंद मार्गों को जल्द खोलने के लिए संबंधित विभागों की मशीनें और टीमें लगातार कार्य कर रही हैं।

एनटीपीसी कोलडैम : हरित ऊर्जा और विकास के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों का निर्वहन प्राथमिकता : एसएस राव

टीएम एक्शन इंडिया मंडी/बिलासपुर। एनटीपीसी कोलडैम परियोजना प्रमुख एसएस राव ने बताया कि सीएसआर के माध्यम से हरित ऊर्जा और सामाजिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए कोलडैम परियोजना प्रमुख ने बताया कि एनटीपीसी की ओर से हर साल यह कोशिश की जाती है कि सामाजिक दायित्व को लेकर देश की महारतन कंपनी एनटीपीसी निष्ठापूर्वक निभाती रहे। उन्होंने बताया कि सामाजिक सरोकारों शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना क्षेत्र के आसपास के स्कूलों में पढ़ाई विद एआई की पहल करते हुए डिजिटल शिक्षा की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। वहीं पर पम्प स्टोरेज पावर प्लांट पीएसपी के तहत मंडी और सोलन जिलों में दो परियोजनाओं की प्रारंभिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर हिमाचल सरकार को स्वीकृति के लिए सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि सीएसआर के तहत कोलडैम



की ओर से 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर 40 गांवों को लाभ पहुंचाया है। इसके अलावा नीट और आईआईटी अभ्याथियों के लिए एआई आधारित ऐस और डिजिटल कोविंग में सहयता की जा रही है। जिससे तीन से पांच सौ विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल के पहले हाइड्रो इंजिनियरिंग कॉलेज के लिए कंपनी की ओर से 70 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध

करवाई गई है। जिससे हिमाचल के विद्यार्थी यहीं पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि एपोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के साथ एनटीपीसी कोलडैम की ओर से कार्याविग, कैंपेइंग और रोकड़ जैसे खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस सुविधाका लाभ उठाकर ग्रामीण खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंडल हॉसिल कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं।

बीडीटीएस ने यूनियन परिसर में वट वृक्ष का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

टीएम एक्शन इंडिया कश्मीर ठाकुर बिलासपुर। बरमाना सीमेंट फैक्ट्री से सीमेंट ढुलाई के लिए अधिकृत ट्रक परिवहन सभा द्वारा यूनियन परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रांसपोर्टर्स ने वट वृक्ष का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रधान जीत राम गौतम, उपप्रधान गंगा सिंह ठाकुर, वरिष्ठ उपप्रधान कमल किशोर व जयसिंह ठाकुर, कैशियर कुलदीप ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष कश्मीर सिंह ठाकुर, मुख्य संरक्षक अनिल हैप्पी, पूर्व प्रधान राकेश ठाकुर, वाइस चेयरमैन शेर सिंह ठाकुर, सह सचिव संतोष ठाकुर, कार्यालय सचिव स्वदेश ठाकुर व नंदलाल ठाकुर सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधान जीत राम गौतम ने



वट वृक्ष की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सावन माह पौधारोपण के लिए अत्यंत उपयुक्त समय है। वहीं वरिष्ठ उपप्रधान कमल किशोर ने भी कहा कि हमें इस दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यह भावी पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। जब हम स्वयं पहल करेंगे तभी आने वाली पीढ़ी भी इसे अपनाएगी। उन्होंने कहा कि समय-समय पर ऐसे आयोजनों के माध्यम से पौधारोपण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ किया जा सके।

गौवंश के स्थायी हल के लिए डीसी बिलासपुर को सौंपा ज्ञापन

टीएम एक्शन इंडिया कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर, कलूर एंविटविस्ट ग्रुप जिला बिलासपुर के युवा कार्यकर्ताओं ने समाजसेवी आयुष भारद्वाज की रहनुमाई में कॉलेज चैक से डीसी आफिस तक एक शांतिपूर्ण रैली निकाली और गौवंश के संरक्षण को लेकर नारे लगाते हुए डीसी बिलासपुर राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आयुष भारद्वाज ने कहा कि पूरे जिला बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों, शहर की सड़कों और बाजारों में बेसालन गायों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनके कारण आए दिन सड़क



दुर्घटनाएं हो रही हैं और गौवंश भी घायल हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ तस्करी के मामले भी बढ़े हैं, जो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था के लिए भी खतरा है। मांगों का जिक्र करते हुए आयुष भारद्वाज ने बिलासपुर में एक

आधुनिक और उचित गोशाला का तुरंत प्रबंध करने की मांग उठाई। उन्होंने गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय नाकों पर सख्त चेकिंग की मांग रखी। नगर परिषद और पंचायतों के सहयोग से सड़कों से गायों को रैस्क्यू कर गोशाला में स्थानांतरित करना आदि की मांग भी प्रभावशाली तरीके से उठाई। उन्होंने बताया कि डीसी बिलासपुर ने उनकी बात को गौर से सुना तथा शोध ही इस विषय पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कलूर एंविटविस्ट ग्रुप के अन्य युवा सदस्य उपस्थित रहे।

रोटरी क्लब कुल्लू के सदस्यों ने हंडीमाचल थेरेपी सेंटर का किया दौरा

टीएम एक्शन इंडिया श्याम कुली

कुल्लू रोटर्री क्लब के सदस्यों ने खिलती कलियों कार्यक्रम के तहत शास्त्री नगर कुल्लू में ‘हंडीमाचल थेरेपी सेंटर’ का दौरा किया व स्पेशल बच्चों के साथ समय बिताया। रोटर्री क्लब कुल्लू के अध्यक्ष रोटेरियन राजीव सिंह ने बताया कि रोटर्री क्लब कुल्लू स्पेशल बच्चों के उत्थान के लिए हमेशा से प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज इस संस्था का दौरा किया गया छ उन्होंने कहा कि इस तरह के स्पेशल बच्चों को भी आम बच्चों की तरह शिक्षा, स्वास्थ व उमंग के साथ जीने का हक है। जरूरतत है जागरूक होने की।। पर जागरूकता के अभाव में बच्चों के माता पिता इस ओर



ध्यान नहीं देते। कहा कि इन बच्चों का किसी न किसी रूप में जरूर सहयोग किया जाना चाहिए छ इस अवसर पर रोटर्री क्लब कुल्लू की ओर से वरिष्ठ रोटेरियन वी0 के0 कपूर,रोटेरियन ए0 जी0 अशुल पराशर,महासचिव रोटेरियन आकाश बांगा,रोटेरियन डाक्टर अभिलाषा ठाकुर,रोटेरियन गगन मल्होत्रा व संस्था के संचालक अश्वोकेट सुरेंद्र मोहन कपूर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

पीएमजीएसवाई-4 में बंजार की 20 सड़कों को 150 करोड़ स्वीकृत : विक्रमादित्य सिंह



शिलान्यास लोक निर्माण मंत्री ने तीन करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास

टीएम एक्शन इंडिया श्याम कुली

कुल्लू, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को बंजार विधानसभा क्षेत्र के दोरे के दौरान लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत वाली महत्वपूर्ण सड़क एवं पुल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने नाबाई के तहत 1.12 करोड़ रुपये की लागत से सुवेहन-शांगड़ सड़क के सुधारोपरण कार्य तथा 1.96 करोड़ रुपये की लागत से तरेहड़ा में वैली ब्रिज के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निष्पारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं, ताकि आम लोगों को शीघ्र बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। तरेहड़ा में

आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यह पुल लंबे समय से क्षेत्र की जनता की प्रमुख मांग थी। पुल बनने से तीन पंचायतों के हजारों लोगों को वर्षभर सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शांगड़ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और सड़क के सुधारोपरण एवं विस्तार से यहां पर्यटन गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़क संर्पाक से स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ेंगे तथा पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। क्षेत्र के पर्यटन को नई गति देने के उद्देश्य से मंत्री ने लारजी से सैंज तथा सैंज-न्यूली-शांगड़ सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे इस मार्ग का व्यापक विकास संभव होगा और पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा और ऑल वेटर कनेक्टिविटी सम्भव होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के अंतर्गत बंजार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से 20 नई सड़कों का निर्माण एवं

जर्जर पुल पर मंडरा रहा हादसे का खतरा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

टीएम एक्शन इंडिया श्याम कुली

कुल्लू मणिकर्ण बस स्टैंड से बाजार को जोड़ने वाला पुल बदहाल, हजारों श्रद्धालु और स्थानीय लोग गुजरना करते हैं आवाजाही मणिकर्ण। धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मणिकर्ण बाजार को बस स्टैंड से जोड़ने वाला पुल लंबे समय से जर्जर हालत में है। पुल की दुर्घटना इतनी खराब हो चुकी है कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद संबंधित विभाग की ओर से पुल की सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इसी पुल से होकर मणिकर्ण बाजार पहुंचते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग भी रोजाना



आवाजाही के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। देवी-देवताओं के स्नान के लिए जाने वाले लोग भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। ऐसे में पुल

की खस्ता हालत लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल लंबे समय से जर्जर हालत में है, लेकिन इसके पुनर्निर्माण को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पुल की स्थिति को देखते हुए यहां किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। लोक निर्माण मंत्री से शीघ्र कार्रवाई की मांग स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मामले का संज्ञान लेकर पुल के पुनर्निर्माण की मांग की है। लोगों का कहना है कि पुल की हालत को देखते हुए इस्का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण करवाया जाए और इसे आम लोगों के लिए सुरक्षित बनाया जाए।

हर दिन के 86400 सेकंड तय करते हैं आपका भविष्य : दित्या ठाकुर

प्रस्तुतियां

टिआना ने कैसियो बजाकर दिखाई अपनी प्रतिभा, 600 छात्रों ने दी शानदार प्रस्तुतियां



टीम एक्शन इंडिया

मनीष सोलन।आनंद विहार स्थित जौनियस ग्लोबल स्कूल का 19वां स्थापना दिवस खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में करीब 600 छात्रों ने भाग लिया और अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कक्षा छठी की छात्राओं कीया, सेहर और आरत के स्वागत प्रार्थना नृत्य से हुई। इसके बाद भव्या, श्रीनिका और शुभांगी ने लजीम की प्रस्तुति दी। आदिक, सिद्धार्थ, कनिष्क और काव्यांश ने श्लोक वंदना प्रस्तुत की। काशवी, अनिकेत और नव्या ने योग की प्रस्तुति देकर सभी की सराहना पाई। कक्षा

दूसरी की छात्रा टिआना ने कैसियो बजाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। कक्षा सातवीं की छात्राओं आव्या, आश्वी, हर्षिता और रशिका ने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। कक्षा तीसरी की छात्रा हितंशी ने अपने विचार रखे। शिक्षा पर आधारित नृत्य-नाटिका में मोक्ष, त्रिशा और प्रनित ने अच्छा संदेश दिया। जुनियर नाटी में रुशांक और अनीषा, जबकि सीनियर नाटी में वैधिका, सनाह और अनाया ने हिमाचली लोकनृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। इस अवसर पर रिटायर्ड प्रिंसिपल दित्या ठाकुर मुख्य अतिथि रही। उन्होंने छात्रों को अनुशासन, समय की अहमियत और जीवन में सफल होने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि जीवन का हर सेकंड

बहुत कीमती होता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को रोज 86,400 सेकंड मिलते हैं। यह ऐसे हैं जैसे हर दिन हमें 86,400 सिक्के मिलें, जिन्हें उसी दिन सही जगह खर्च करना होता है। इसलिए समय का सही इस्तेमाल ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपना लक्ष्य तय करें, रोज मेहनत करें, खुद पर भरोसा रखें और हमेशा अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि अग्रेजी केवल एक विषय नहीं बल्कि एक भाषा है। इसलिए इसे सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि अच्छी तरह बोलने, समझने और ज्ञान बढ़ाने के लिए सीखना चाहिए। मुख्य अतिथि ने स्कूल में लगाई गई

कालाअंब की स्टील फैक्ट्री में गिरकर कर्मचारी की मौत, प्रबंधन पर मामला दर्ज

एसपी जैरथ

नाहन औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब स्थित एक स्टील फैक्ट्री में मेटेनेंस कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। ओवरहेड लैंक क्रेन पर काम कर रहे एक कर्मचारी की करीब 30 फीट ऊंचाई से गिरने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संदीप कुमार निवासी दोराहा, जिला लुधियाना (पंजाब), जो एच.एम. स्टील में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, ने पुलिस थाना कालाअम्ब में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में बताया गया कि 26 जुलाई 2026 को कंपनी के सीसीएम प्लांट में ओवरहेड लैंक क्रेन पर मेटेनेंस कार्य चल रहा था। इस दौरान कई कर्मचारी क्रेन पर काम कर रहे थे।

पीलिया, स्क़ब टायफ़स एवं एचपीवी टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित

निर्देश

उपायुक्त ने समीक्षा बैठक में दिए प्रभावी रोकथाम और जनजागरूकता के निर्देश



टीम एक्शन इंडिया

मंडी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में पीलिया, स्क़ब टायफ़स तथा एचपीवी टीकाकरण अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपूर्व देवगन ने स्वास्थ्य विभाग सहित

सभी संबंधित विभागों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी एडवाइजरी का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि मानसून के दौरान स्क़ब टाइफ़स के मामलों में वृद्धि की संभावना रहती है। ऐसे में सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, समय पर जांच, उपचार तथा सदिध मामलों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की

तथा सामुदायिक जागरूकता ही इन बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने सभी नागरिकों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाते देने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ दिनेश ठाकुर ने बताया कि स्क़ब टाइफ़स एक जीवाणु जनित रोग है, जो संक्रमित माइट (चिगर) के काटने से फैलता है।

29 जुलाई को रिलीज होगा हिमाचली लोकगीत ‘ध्याड़ा काटणा



टीम एक्शन इंडिया

मंडी। हिमाचली लोकसंगीत और संस्कृति को समर्पित एक नई संगीतमय प्रस्तुति ‘ध्याड़ा काटणा’ का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। लीप म्यूजिक के बैनर तले निर्मित यह बहुप्रतीक्षित हिमाचली लोकगीत 29 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। गीत को अपनी मधुर आवाज से

रविकांत चंदेल ने सजाया है, जबकि इसके गीत एवं संगीत रचना एसडी कुशपट्ट द्वारा की गई है। गीत का संगीत प्रत्येक कुमार ने तैयार किया है, जिसमें हिमाचली लोकधुनों की मिठास और आधुनिक संगीत का सुंदर समन्वय देखने को मिलेगा। गीत का निर्देशन अनिल महंत ने किया है। वीडियो में लवीशा

पंडित मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। पंकज वैद्य ने डीओए, संपादन एवं कलर ग्रेडिंग का कार्य संभाला है। निशांत ठाकुर ने स्क्रीनलेय तथा हितेश कुमार ने लाइन प्रोड्यूसर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लीप म्यूजिक की यह प्रस्तुति हिमाचल की लोकसंस्कृति, परंपराओं और भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाती है। टीम को उम्मीद है कि यह गीत अपने मधुर संगीत, अर्थपूर्ण बोल और आकर्षक फ़िल्मांकन के कारण दर्शकों और श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान बनाएगा। ध्याड़ा काटणा का आधिकारिक वीडियो 29 जुलाई को केवल लीप म्यूजिक के आधिकारिक यू ट्यूब चैनल पर रिलीज होगा। संगीत प्रेमियों से इस विशेष प्रस्तुति को देखने, सुनने और अपना स्नेह एवं आशीर्वाद देने की अपील की गई है।

गुरु रविदास जी ने समरस, समान और भेदभाव-मुक्त समाज का दिया संदेश

टीम एक्शन इंडिया

मनीष

सोलन/बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी के समरस संकल्प अभियान के अंतर्गत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर बढ़ी में जिला बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रतन पाल, जिला प्रभारी राजपाल तथा सह प्रभारी संदीपनी भारद्वाज सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजीव कटवाल ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी केवल एक महान संत ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की, जहां किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति, वर्ग या जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, चरित्र और भक्ति से तय



हो। उन्होंने जीवनभर ऊंच-नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया तथा प्रेम, सेवा, सत्य और समानता का संदेश दिया। संजीव कटवाल ने गुरु रविदास जी के प्रसिद्ध ‘बेगमपुरा’ के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु जी ने एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना की थी, जहां किसी प्रकार का दुख, भेदभाव, अन्याय, कर या भय न हो तथा प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और समान अधिकारों के साथ जीवन व्यतीत कर सके। उनका यह संदेश आज भी सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

सिरमौर में एंटी-चिंट्र अभियान – एक्शन प्लान में वसूला 51 हजार जुर्माना,65 चालान कटे

एसपी जैरथ

नाहन राज्यव्यापी एंटी-चिंट्र अभियान – एक्शन प्लान फेज-II के अंतर्गत विशेष जांच अभियान चलाया गया। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि अभियान के तहत 200 दुकानदारों की जांच की गई। इस दौरान सिगरेट एवं बीड़ी (हिप्र.) अधिनियम, 2016 के तहत खुले सिगरेट बेचने के जुर्म में 6 चालान किए गए और 30,000 जुर्माना वसूला गया। एसपी ने बताया कि कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत कटे 59 चालान हुए और 21,100/- * जुर्माना वसूला गया। जुर्माना स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग द्वारा वसूल किया गया नेगी ने बताया कि यह अभियान तंबाकू उत्पादों की बिक्री में नियमों के उल्लंघन की जांच और जिले में चल रहे नशा विरोधी अभियान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाया गया।

बिलासपुर मंडी में पॉड स्टोरेज जलविद्युत योजना की तैयारी, कोल डैम से जुड़ना नया ऊर्जा और पर्यटन विकास मॉडल



टीम एक्शन इंडिया

कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। बिलासपुर मंडी जिला जल्द ही ऊर्जा उत्पादन और पर्यटन विकास के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने जा रहा है। पम्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर स्कीम के तहत एनटीपीसी के कोल डैम में एक महत्वपूर्ण परियोजना प्रस्तावित की गई है। बताते चले यह योजना सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पांथा धार पर भी संभावनाएं तलाशी जा रही है। जिससे क्षेत्र में बिजली उत्पादन की क्षमता और अधिक सुदृढ़ होगी। वर्तमान में कोल डैम से लगभग 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है जबकि इस डैम से तत्पानी तक लगभग 40 किलोमीटर लंबी झील भी बनी हुई है। इस नई योजना के लागू होने से न केवल ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी जिला बिलासपुर को नया आयाम मिलेगा। इस योजना की विशेषता यह है कि इसमें

सोलर पावर का भी उपयोग किया जाएगा। दिन के समय जब सौर ऊर्जा सस्ती और अधिक उपलब्ध होती है तब झील से पानी को लिफ्ट कर ऊपर स्थित जलाशय में संग्रहित किया जाएगा। इसके बाद, जब बिजली की मांग अधिक होगी तब इस पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन के माध्यम से बिजली उत्पादन की जाएगी। इस प्रकार यह योजना ऊर्जा के भंडारण और उत्पादन दोनों में सहायक सिद्ध होगी। हिमड्रा के निदेशक जितेंद्र चंदेल इस महत्वकांक्षी योजना को कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखरू के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पंड स्टोरेज तकनीक भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी खासकर तब जब सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

कसौली की वादियों में पर्यावरण की अलख: गिलबर्ट ट्रेल में पौधारोपण से दिया स्वच्छता का संदेश



टीम एक्शन इंडिया

विशाल

कसौली। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाते हुए ऐतिहासिक गिलबर्ट ट्रेल में पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस विशेष अभियान में सेट मैरी स्कूल के इको क्लब के बच्चों और शिक्षकों ने बड़े संख्या के साथ भाग लिया और पौधे रोए। इस मौके पर छावनी परिषद (केंट बोर्ड) के कर्मचारी, वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक रोहित पुरी और शुभम सुंद ने आयोजन को सुचारु रूप से संपन्न

करवाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। आयोजकों ने इस मुहिम को सफल बनाने के लिए छावनी परिषद की मुख्य अधिशासी अधिकारी (एचए) सुमन सोरभ और ब्रिगेडियर संपीक मदान, एस एच ओ कसौली घनश्याम अत्रि का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन और बहुमूल्य योगदान के बिना इस स्तर पर पौधारोपण अभियान को सफल बनाना संभव नहीं था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कसौली की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना और युवा पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है।

महापौर सुषमा शर्मा एवं पार्षद रोहित भारद्वाज ने वार्ड नंबर-4 सलोगड़ा में किया औचक निरीक्षण

टीम एक्शन इंडिया

मनीष

सोलन। नगर निगम सोलन की महापौर सुषमा शर्मा एवं वार्ड नंबर-4 के पार्षद रोहित भारद्वाज ने आज सलोगड़ा क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर सफाई व्यवस्था की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सुषमा शर्मा ने कहा कि ‘हमारा वार्ड स्वच्छ रहेगा, तभी हमारे लोग स्वस्थ रहेंगे।’ उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना नगर निगम की प्राथमिकता है। प्रत्येक नागरिक का भी यह दायित्व है कि वह अपने आसपास स्वच्छता



बनाए रखने में सहयोग करें। पार्षद रोहित भारद्वाज ने कहा कि वार्ड नंबर-4 को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे

हैं। निरीक्षण के दौरान जिन स्थानों पर सफाई की आवश्यकता थी, वहां तत्काल सफाई कार्य करवाया गया तथा भविष्य में नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने महापौर एवं पार्षद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में पहली बार किसी महापौर को उनके क्षेत्र में स्वयं आकर निरीक्षण करते हुए देखा है। उन्होंने नगर निगम द्वारा किए जा रहे स्वच्छता कार्यों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इसी प्रकार जनहित के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की कि वे स्वच्छ भारत अभियान को जन-आंदोलन बनाते हुए अपने आसपास सफाई बनाए रखें और नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें।

संक्षिप्त खबरें

प्राइवेट गाड़ियों में अवैध टैक्सी चालने पर कार्रवाई की मांग, सोसायटी ने उपायुक्त को सौंपा झापन



टीम एक्शन इंडिया

एसपी जैरथ

नाहन, सिरमौर टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर्स सोसायटी, नाहन ने उपायुक्त सिरमौर को झापन सौंपकर जिले में प्राइवेट वाहनों का टैक्सी के रूप में हो रहे कथित अवैध संचालन रोकने की मांग उठाई है। सोसायटी का कहना है कि पिछले करीब दो वर्षों से टैक्सी स्टैंडों की जांच के नाम पर टैक्सी चालकों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि सरकारी विभागों में निजी वाहनों का टैक्सी की तरह इस्तेमाल लगातार जारी है। सोसायटी ने झापन में कहा है कि इससे टैक्सी संचालकों की आजीविका प्रभावित हो रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि कई सरकारी विभागों में निजी गाड़ियों

का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। सोसायटी ने प्रशासन से मांग की है कि सरकारी विभागों में टैक्सी के रूप में चल रही निजी गाड़ियों की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान और कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं ताकि टैक्सी संचालकों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जा सके। सोसायटी ने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन इस मामले का शीघ्र संज्ञान लेकर उचित कदम उठाएगा, जिससे वैध टैक्सी संचालकों के हितों की रक्षा हो सके प्रतिनिधि मंडल निजी मैडम न्याय से मिला जिसमें टैक्सी सोसाइटी के अध्यक्ष आकर्षण शर्मा, आदि।

70 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 31 जुलाई को

टीम एक्शन इंडिया

सोलन। जिला सोलन के मॉडल कैरियर सेंटर सोलन नजदीक डीस्ट्रॉफी हास्पिटल जटोली (जिला रोजगार कार्यालय) सोलन में 31 जुलाई, 2026 को 70 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि एलआईसी ऑफ इंडिया, सोलन बीमा स्थली के (50) पदों, व तपन इंडस्ट्रीज सोलन, सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव करेस्मर, टीम लीडर के (20) रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उक्त

पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट व आयु 18 से 37 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पदों की विस्तृत जानकारी आवेदक विभागीय पोर्टल ईईई.एम.आई.एस. में प्राप्त कर सकते हैं। सभी योग्य एवं इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल ईईई.एम.आई.एस. पर कैडिडेट लॉगइन टैब के माध्यम से पंजीकृत करने के उपरांत अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पर अधिसूचित रिकवियों के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन से पूर्व प्रत्येक आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

निर्माणाधीन क्षेत्रीय अस्पताल में दो वर्ष से अधिक की देरी, जनता इलाज के लिए परेशान-शैलेन्द्र

टीम एक्शन इंडिया

मनीष

सोल। भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल के अध्यक्ष शैलेन्द्र ने कहा कि सोलन के कबड़े बाईपास में निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले आधुनिक क्षेत्रीय अस्पताल का शिलान्यास वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर तथा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सहजल द्वारा किया गया था। इस महत्वकांक्षी परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत 90 करोड़ 30 लाख रुपये के बीच थी। उन्होंने कहा कि अस्पताल का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन समय पर कार्य पूरा नहीं हो सका। इसके बाद सरकार ने नई समय-सीमा अप्रैल 2026 तक की, किंतु वह समय-सीमा भी समाप्त हो चुकी है और आज भी

अस्पताल का निर्माण अधूरा है। दो वर्षों से अधिक की देरी के बावजूद निर्माण कार्य में अपेक्षित गति देखने को नहीं मिली। शैलेन्द्र ने कहा कि जनता को बार-बार निरीक्षण और फोटो सेशन के माध्यम से केवल आश्वासन दिए गए, लेकिन धरातल पर काम की गति कभी नहीं बढ़ी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री धनीराम शांडिल ने ने अपना उत्तराधिकारी चुनने में जितनी तत्परता दिखाई, यदि उतनी ही गंभीरता और तेजी विकास कार्यों को गति देने में दिखाई होती, तो आज सोलन की यह दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने कहा कि सोलन-सपाटू मार्ग का भी फरवरी माह में निरीक्षण कर केवल फोटो खिंचवाए गए और लोगों को बड़े-बड़े आश्वासन दिए गए, लेकिन आज तक इस सड़क के सुधार के लिए बजट का कोई टैग प्रवाधान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप जनता आज भी बर्हान सड़क पर सफर करने को मजबूर है।

नॉर्थ जोन शॉपिंग वैपियनशिप में आर्यन सकलानी ने किया नेशनल वैपियनशिप के लिए क्वालिफाई

एसपी जैरथ

नाहन हिमाचल प्रदेश पुलिस शूटिंग क्लब, धौलाकुआं के सदस्य आर्यन सकलानी ने क्वालिफाइंग राउंड में 25 टारगेट (बर्ड्स) में से 19 पर सटीक निशाना साधकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्थान सुनिश्चित किया। कोच ने उपलब्धि को मेहनत और अनुशासन का परिणाम बताया शूटिंग क्लब के कोच एवं महासचिव सुरेश लोहान ने बताया कि अर्यन की यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि क्लब को उम्मीद है कि आर्यन नेशनल शूटिंग वैपियनशिप में भी बेहतर प्रदर्शन कर प्रवेश और जिला सिरमौर का नाम रोशन करेंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस शूटिंग क्लब ने आर्यन सकलानी को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

हरित एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

टीम एक्शन इंडिया
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 लागू की गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड

स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 के तहत छह लाभार्थियों को सब्सिडी चेक वितरित किए और 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पांच अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी एवं स्वीकृति प्रक्रिया भी परिवहन विभाग की ओर से पूर्ण की जा चुकी है। धामी ने कहा कि यह पहल केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि प्रदेश में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को



बढ़ावा देने और डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को

कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि



जलवायु परिवर्तन को चुनौती से निपटने के लिए विकास और

पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हरित ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार भी इसी सोच के अनुरूप स्वच्छ परिवहन, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, ईवी चार्जिंग स्टेशन और आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली के विकास पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को हरित विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया गया है तथा कुल लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव परिवहन रविनाथ रमन और अन्य अधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मप्र: राज्य के सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2, 480 करोड़ रुपये स्वीकृत

टीम एक्शन इंडिया
भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याण को गति देने के लिए लगभग 2 हजार 480 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई। बैठक में खेल गतिविधियों, सिंचाई, महिला सशक्तीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और किसान कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में अक्टूबर 2026 में भोपाल में 'महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी' के भव्य आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य की खेल अवसरचरणा और पर्यटन को वैश्विक पहचान मिलेगी। कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए रिहन्द एवं मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजनाओं और किसानों को समर्थन मूल्य पर



बोनस भुगतान योजना की निरंतरता को मंजूरी मिली। उन्होंने बताया कि प्रदेश को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने के उद्देश्य से आईआईएसईआर भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' और आईटी पार्कों के विकास के लिए 857 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इन निर्णयों में आई टी पार्क की स्थापना के वर्ष 2031 तक संचालन की निरंतरता की स्वीकृति महत्वपूर्ण है, इसके तहत करीब 8000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। 'मिशन

शक्ति' के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए 198 करोड़ रुपये, कर्मचारी कल्याण एवं पेंशन योजनाओं के लिए 982 करोड़ रुपये और ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा के निरीक्षकालय के नवीन वृत्त कार्यालय और नारायणगढ़ में 9 नए न्यायिक पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
अक्टूबर में महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026 का आयोजन
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2026 में भोपाल के

स्वीकृति
भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी के आयोजन के लिए 18.74 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति

लिए अधिकृत किया गया है। प्रतियोगिता वर्ष 2010 से निरन्तर दो वर्ष के अन्तराल में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य एशियाई महिला हॉकी टीमों की प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026 में एशिया की प्रमुख 6 महिला टीमों (भारत, चीन, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया, एवं थाईलैण्ड) के लगभग 200 खिलाड़ी व सपोर्ट स्टाफ के सम्मिलित होने की संभावना है। यह अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता हॉकी इण्डिया और खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की

जाएगी। अनुबंध अनुसार हॉकी इण्डिया को खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 'पेजेंटिंग पार्टनर' राइट्स के लिए 11 करोड़ रुपए दिये जाएंगे। अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए विभाग द्वारा 7 करोड़ 74 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा। इस प्रकार आयोजन पर लगभग 18 करोड़ 74 लाख रुपये का व्यय होना संभावित है। भोपाल के बरखेड़ा नाथू में अन्तरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नवीन एवं आधुनिक तकनीकों के अनुरूप अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रमुख प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए तैयार किया गया है। एशिया स्तर की अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन से वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश में निर्मित खेल अधोसंरचना का प्रचार प्रसार होगा। इससे प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों के मनोबल में वृद्धि होगी और एशिया के प्रमुख देशों से सम्मिलित हुई टीमों के खिलाड़ियों के भोपाल आगमन से प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

असम के सभी विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक माह की सैलरी का किया दान



टीम एक्शन इंडिया
गुवाहाटी। असम विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने कहा कि असम में आई विनाशकारी बाढ़ से खासकर ऊपरी असम के तीन जिलों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सरकार के साथ ही विभिन्न संगठन भी अपनी ओर से मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में मैं (रंजीत दास) और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. हाब्ले तेरन ने अपने एक माह का वेतन बाढ़ पीड़ितों के लिए दान करने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष दास ने साथ ही कहा कि विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों ने भी अपनी एक दिन के वेतन को बाढ़ प्रभावितों की

मदद के लिए देने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष ने इस आपदा में सभी से एकजुट होकर प्रभावितों की मदद का आह्वान किया। अध्यक्ष के इस कदम का सदन में उत्थित सभी विधायकों ने मेज थपथा कर स्वागत किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारीका ने कहा कि भाजपा के सभी विधायकों ने भी अपने एक महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। साथ ही कहा कि असम प्रदेश भाजपा मुख्यालय से बाढ़ पीड़ित महिलाओं के लिए एक लाख 70 हजार मेखला चादर और 1.50 लाख मच्छरदानी भेजा गया है। इस बीच टीएमसी के एकमात्र विधायक शेखान अली अहमद ने भी एक माह का वेतन देने की घोषणा की।

नई ऊर्जा से भरपूर युवाओं के नए विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण - मुख्यमंत्री



टीम एक्शन इंडिया
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा से लेकर खेल, रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक युवाओं के हर सपने को पूरा करने में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार पेरपलीक पर प्रभावी रोक, रिकॉर्ड सरकारी भर्तियों, स्टार्टअप को प्रोत्साहन तथा कोशल विकास के माध्यम से युवाओं का उज्ज्वल भविष्य बनाने में सहयोगी बन रही है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सपनों की उड़ान कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि विचारशील, अनुशासित एवं संस्कारवान युवा विकसित भारत-विकसित राजस्थान के आधार हैं। युवा नए विचार और नई ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हमारी सरकार युवाओं से संवाद कर बजट में उनके बहुमूल्य

निशाना साधा
अनुशासन, संस्कारों को आत्मसात करें और आत्मविश्वास के साथ उनके सपनों को साकार करें

सुझावों को शामिल करती है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों को और बेहतर बनाने के लिए युवाओं के साथ इस तरह के संवाद बेहद महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकार युवाओं के सुझावों पर विचार कर आगामी योजनाएं तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि माता-पिता बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं, युवा उनसे सीख लेकर लगन, मेहनत, अनुशासन, संस्कारों को आत्मसात करें और आत्मविश्वास के साथ उनके सपनों को साकार करें।

एचपीवी सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा का मजबूत सामाजिक कवच: आनंदीबेन

टीम एक्शन इंडिया
वाराणसी। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को वाराणसी के सिगरा स्थित रूद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर सरकार द्वारा संचालित एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष पूर्ण एवं 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन लगाई गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वयं बालिकाओं को टीकाकरण के



उपरांत प्रमाण-पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान आराध्या शाह, अर्पिता कुमारी,

आधारशीला
स्वस्थ बेटी ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है

आधारशीला
स्वस्थ बेटी ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है

समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि एचपीवी वैक्सीन बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाला एक प्रभावी एवं सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा कवच है। उन्होंने बालिकाओं एवं अभिभावकों से अपील करते हुए कहा, रूढ़िरे मत, आप सामना कीजिए। यह

वैक्सीन आपको सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि यह टीका भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को कम करने में सुरक्षित एवं प्रभावी है। उन्होंने अभिभावकों से किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रांति अथवा अनावश्यक आशंकाओं से दूर रहने तथा अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण कराने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने समाज में बेटों और बेटियों के बीच भेदभाव की मानसिकता समाप्त करने पर बल देते हुए कहा कि स्वस्थ बेटी ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है।

राज्यपाल बागडे से यूडीएच मंत्री खर्षा और चिकित्सा मंत्री खींवर की शिष्टाचार भेंट



जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मंगलवार को लोकभवन में प्रदेश के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्षा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवर ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने राज्यपाल बागडे का अभिवादन किया। यह भेंट शिष्टाचार मुलाकात के रूप में हुई।

नीतीश ने पूर्व सुरक्षा पदाधिकारी बसंत सिंह का जाना हाल

कुशलक्षेम
उपचाररत पूर्व सुरक्षा पदाधिकारी बसंत सिंह से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना

टीम एक्शन इंडिया
पटना। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार मंगलवार को पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) परिसर स्थित इंदिरा गांधी आर्युर्विज्ञान संस्थान परिसर



(आईजीआईसी) पहुंचे। यहां उन्होंने उपचाररत पूर्व सुरक्षा पदाधिकारी बसंत सिंह से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने संस्थान के निदेशक डॉ. सुनील कुमार से बसंत सिंह के स्वास्थ्य

की विस्तृत जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देने तथा मरीज को सभी आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।

इस दौरान नीतीश कुमार ने अस्पताल में मौजूद लोगों से सख्तिप वातचीत भी की और उपचार व्यवस्था की जानकारी ली। उनके साथ बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ भी मौजूद रहे।

एनडीए की बैठक से पहले मुख्यमंत्री शुभेंद्र से मिले एनसीपीआई सांसद सुदीप बंदोपाध्याय

टीम एक्शन इंडिया
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने सोमवार रात राज्य सचिवालय नवानन में मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी से बंद कमरे में मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के सांसद मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बैठक में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार, करीब एक घंटे तक चली इस बैठक को राजनीतिक दृष्टि से



काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय या सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शुभेंद्र

अधिकारी पहले नई दिल्ली जाकर एनसीपीआई के सांसदों से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में अपनी यात्रा रद्द कर दी। इसके बाद उन्होंने कुछ वरिष्ठ एनसीपीआई सांसदों से फोन पर बातचीत कर

यात्रा टली
मुख्यमंत्री और पार्टी सांसदों के बीच प्रस्तावित बैठक फिलहाल टाल दी गई है

दिल्ली नहीं पहुंच पाने की जानकारी दी। एनसीपीआई के एक वरिष्ठ सांसद ने बताया कि मुख्यमंत्री और पार्टी सांसदों के बीच प्रस्तावित बैठक फिलहाल टाल दी गई है। हालांकि पार्टी के सभी सांसद तय कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे। हाल के

दिनों में तुणमूल कांग्रेस से अलग होकर 20 सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने के बाद इस नई पार्टी की राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ी है। इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर अलग संसदीय दल के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया था। साथ ही लोकसभा में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बैठने की भी मांग की थी, जिससे भाजपा नीत गठबंधन के साथ उनकी निकटता की चर्चा तेज हो गई। मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाग लेकर केंद्र की सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ अपने बढ़ते राजनीतिक संपर्क के संकेत दिए थे।

रायपुर : मुनगा बनेगा सुपोषित छत्तीसगढ़ का आधार : लक्ष्मी राजवाड़े

टीम एक्शन इंडिया
रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों से वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक मुनगा (सहजन) पौधे लगाने की अपील की है, ताकि कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण हो सके। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों और घरों में रसुपोषण वृक्ष-मुनगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों और माताओं को स्थानीय पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि,



मुनगा, जिसे रमदर्स ट्रीर कहा जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन से भरपूर है और यह बच्चों के विकास, मातृ स्वास्थ्य तथा एनीमिया रोकथाम में अत्यंत उपयोगी है। सरकार पोषण

सुधार को जनभागीदारी आधारित अभियान बना रही है। आंगनबाड़ी और घरों में मुनगा पौधरोपण से पोषण जागरूकता और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जनप्रतिनिधियों से अपील- मंत्री ने सांसदों, विधायकों, पंचायत प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में मुनगा पौधरोपण का नेतृत्व करने का आग्रह किया। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक पौधरोपण कर सुपोषण वाटिका विकसित करने पर जोर दिया।

